



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-13] रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 सितम्बर, 2012 ई0 (भाद्रपद 10, 1934 शक सम्वत्) [संख्या-35

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	541—544	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	1181—1196	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	—	975
स्टोर्स पर्वेज—स्टोर्स पर्वेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

वित्त अनुभाग—8

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण

31 जुलाई, 2012 ई0

संख्या 728/2012/16(100)/XXVII(8)/12 टी0सी0—तात्कालिक प्रभाव से वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत डिप्टी कमिश्नर स्तर के अधिकारियों का स्थानान्तरण एतद्वारा निम्नानुसार किया जाता है:—

क्र0 सं0 अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती का पद/स्थान	नवीन तैनाती का पद/स्थान
1. श्री राकेश टंडन	डिप्टी कमिश्नर/(क0नि0)—प्रथम, वाणिज्य कर, हरिद्वार	डिप्टी कमिश्नर/क0नि0—1, रुद्रपुर
2. श्री एम0एस0 ग्वाल	डिप्टी कमिश्नर/(क0नि0)—पंचम, वाणिज्य कर, देहरादून	डिप्टी कमिश्नर/(वि0अनु0शा0), वाणिज्य कर, रुद्रपुर
3. श्री एस0पी0 नौटियाल	डिप्टी कमिश्नर/(क0नि0)—द्वितीय, वाणिज्य कर, काशीपुर	डिप्टी कमिश्नर/(प्रर्व0), वाणिज्य कर, हल्द्वानी
4. श्री ललित कुमार खुल्वे	डिप्टी कमिश्नर/उच्च न्यायालय कार्य, नैनीताल	डिप्टी कमिश्नर/क0नि0—1, वाणिज्य कर, काशीपुर
5. श्री राजेश गिल	डिप्टी कमिश्नर/(प्रर्व0) प्रथम, वाणिज्य कर, देहरादून	डिप्टी कमिश्नर/(प्रर्व0), वाणिज्य कर, हरिद्वार
6. श्री वी0पी0 सिंह	डिप्टी कमिश्नर/(प्रर्व0), वाणिज्य कर, हरिद्वार	डिप्टी कमिश्नर/(क0नि0)—पंचम, देहरादून एवं आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, देहरादून
7. श्री प्रवीण कुमार	डिप्टी कमिश्नर/(प्रर्व0), वाणिज्य कर, हल्द्वानी	डिप्टी कमिश्नर/(क0नि0)—प्रथम, वाणिज्य कर, देहरादून
8. श्री ठाकुर रणवीर सिंह	डिप्टी कमिश्नर/क0नि0—1, वाणिज्य कर, काशीपुर	डिप्टी कमिश्नर/क0नि0—3, वाणिज्य कर, काशीपुर
9. श्री अजय सिंह	डिप्टी कमिश्नर/क0नि0—1, वाणिज्य कर, रुद्रपुर	डिप्टी कमिश्नर/राज्य प्रतिनिधि, हल्द्वानी
10. श्री अनुराग मिश्रा	डिप्टी कमिश्नर/क0नि0—6, वाणिज्य कर, देहरादून	डिप्टी कमिश्नर/(क0नि0)—प्रथम, वाणिज्य कर, हरिद्वार
11. श्री निशिकान्त सिंह	डिप्टी कमिश्नर/(वि0अनु0शा0), वाणिज्य कर, रुद्रपुर	डिप्टी कमिश्नर/(प्रर्व0), वाणिज्य कर, काशीपुर
12. श्री आर0एल0 वर्मा	डिप्टी कमिश्नर/(प्रर्व0), वाणिज्य कर, देहरादून	डिप्टी कमिश्नर/राज्य प्रतिनिधि, देहरादून
13. श्रीमती स्मिता	डिप्टी कमिश्नर/क0नि0—3, वाणिज्य कर, काशीपुर	डिप्टी कमिश्नर/उच्च न्यायालय कार्य, नैनीताल
14. श्री शशिकान्त आर्य	डिप्टी कमिश्नर/राज्य प्रतिनिधि, देहरादून	डिप्टी कमिश्नर/(प्रर्व0), वाणिज्य कर, देहरादून
15. श्री अनुप गुप्ता	डिप्टी कमिश्नर/राज्य प्रतिनिधि, हल्द्वानी	डिप्टी कमिश्नर/(क0नि0)—6, वाणिज्य कर, देहरादून
16. श्री जगदीश सिंह	डिप्टी कमिश्नर/(प्रर्व0), वाणिज्य कर, काशीपुर	डिप्टी कमिश्नर/(क0नि0)—द्वितीय, वाणिज्य कर, काशीपुर

उपर्युक्तानुसार स्थानान्तरित अधिकारी तत्काल अपनी नई तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण

31 जुलाई, 2012 ई0

संख्या 729/2012/16(100)/XXVII(8)/12 टी0सी0—तात्कालिक प्रभाव से वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत ज्वाइंट कमिश्नर स्तर के अधिकारियों का स्थानान्तरण एतद्वारा निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती का पद/स्थान	नवीन तैनाती का पद/स्थान
1.	श्री एन0एस0 पाँगती	ज्वाइंट कमिश्नर (अपील), प्रथम, वाणिज्य कर, हल्द्वानी	ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक), वाणिज्य कर, हल्द्वानी
2.	श्री पीयूष कुमार	ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, देहरादून सम्भाग, देहरादून	ज्वाइंट कमिश्नर, मुख्यालय, देहरादून
3.	श्री एन0सी0 शर्मा	ज्वाइंट कमिश्नर (अपील), द्वितीय, वाणिज्य कर, देहरादून	ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्रर्व0), वाणिज्य कर, कुमाऊँ जोन, रुद्रपुर
4.	श्री हनुमान सिंह नबियाल	ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0), वाणिज्य कर, हल्द्वानी	ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0), वाणिज्य कर, काशीपुर
5.	श्री एन0एस0 दताल	ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्रर्व0) वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन, हरिद्वार	ज्वाइंट कमिश्नर (अपील), द्वितीय, देहरादून
6.	श्री बी0बी0 मठपाल	ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्रर्व0) वाणिज्य कर, कुमाऊँ जोन, रुद्रपुर	ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0), वाणिज्य कर, देहरादून सम्भाग, देहरादून
7.	श्री विपिन चन्द्र	ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0), वाणिज्य कर, काशीपुर	ज्वाइंट कमिश्नर (अपील), प्रथम, वाणिज्य कर, हल्द्वानी
8.	श्री ए0सी0 राम	ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय, देहरादून	ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्रर्व0), वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन, हरिद्वार

उपर्युक्तानुसार स्थानान्तरित अधिकारी तत्काल अपनी नई तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

राधा रतूड़ी,
सचिव।

वित्त अनुभाग-6

विज्ञप्ति/सेवा निवृत्ति

08 अगस्त, 2012 ई0

संख्या 324/XXVII(6)/2012—वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारी अपने नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित तिथि को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री शरद चन्द्र पाण्डेय	निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, अपर सचिव, वित्त	31.01.2013
2.	श्री चित्रमणि भटगंई	वित्त नियन्त्रक, लघु सिंचाई, दे0दून	28.02.2013

1	2	3	4
3.	श्री महादेव प्रसाद	उप निदेशक, लेखा एवं हकदारी (शिविर कार्यालय), हल्द्वानी	31.03.2013
4.	श्री किशोर कुमार यादव	कोषाधिकारी, हरिद्वार	31.01.2013
5.	श्री फूल सिंह	वित्त अधिकारी, गन्ना एवं चीनी आयुक्त कार्यालय	31.01.2013
6.	श्री नत्थी लाल बहुगुणा	वरिष्ठ वित्त अधिकारी, सीमेट, देहरादून	30.09.2012
7.	श्री खुशाल लाल	वित्त अधिकारी, डी0आर0डी0, चमोली	31.01.2013
8.	श्री बच्ची दत्त जोशी	वित्त अधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी, नैनीताल	28.02.2013

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 सितम्बर, 2012 ई0 (भाद्रपद 10, 1934 शक सम्बत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(फार्म-अनुभाग)

विज्ञप्ति

05 मार्च, 2012 ई0

पत्रांक 8144/आयु0कर, उत्तरा0/फार्म-अनु0/2011-12/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून-उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 30 (12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्र (प्ररूप-XVI), जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ:-

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज व क्रमांक
1.	सर्वश्री सैनचूरी मेटल रिसाईकलिंग प्रा0लि0, सिडकुल, हरिद्वार	प्ररूप-XVI (14)	U.K.VAT-B2009 0678633, 0678670, 0838571, 1477230, 1477231, 1477252, 1477275, 1477288, 1552176, 1552195, 1743952, 1744051, 1744052, 1744053
2.	सर्वश्री टी0आई0डी0सी0 इण्डिया, खसरा नं0 230-231, ग्राम गंगनौली, लक्सर (हरिद्वार)	प्ररूप-XVI (03)	U.K.VAT-K2010 0836588, 1164996, 1164998
3.	सर्वश्री अभिप्रिया बिजनेस (इण्डिया) प्रा0लि0, प्लॉट सं0-9, सैक्टर-6, पन्तनगर (ऊधमसिंह नगर)	प्ररूप-XVI (03)	U.K.VAT-B2009 0479344, 0479364, 0479365
4.	सर्वश्री आर0के0 इण्डस्ट्रीज, लक्सर रोड, कनखल, हरिद्वार	प्ररूप-XVI (01)	U.K.VAT-K2010 0909950
5.	सर्वश्री राखी गारमेन्ट्स एण्ड फुटवियर्स, ग्राम तरपाली, पोस्ट बगेली, थैलीसैण (पौड़ी गढ़वाल)	प्ररूप-XVI (01)	U.K.VAT-K2010 0749757

वी0के0 सक्सेना,
अपर आयुक्त, वाणिज्य कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विज्ञप्ति

10 जुलाई, 2012 ई0

पत्रांक 1600/आयु0कर, उत्तरा0/फार्म-अनु0/2012-13/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून-उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 30 (12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्र (प्ररूप-XVI), जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करती हूँ:-

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज व क्रमांक
1.	सर्वश्री ब्राइट सन्नी पाईन्स, जयहरीखाल (पौड़ी गढ़वाल)	प्ररूप-XVI (05)	U.K.VAT-K2010 - 1282872 to 1282876
2.	सर्वश्री श्री बालाजी एजेन्सीज, 79, भण्डारी बाग, देहरादून	प्ररूप-XVI (01)	U.K.VAT-K2010-1514369

कुमकुम गुप्ता,
अपर आयुक्त, वाणिज्य कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विज्ञप्ति

16 जुलाई, 2012 ई0

पत्रांक 1690/आयु0क0 उत्तरा0/फार्म-अनु0/2012-13/केन्द्रीय फार्म-सी/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून-केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तराखण्ड), नियमावली, 2006 के नियम 8 के उपनियम 13 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित "फार्म-सी" जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन फार्मस के प्रयोग को अवैध घोषित करती हूँ:-

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज व क्रमांक
1.	सर्वश्री सिप्ला लि0, बी-21, 22, ट्रान्सपोर्ट नगर, देहरादून	(Form-C)-01	U.K. VAT/C-2007- 420132

विज्ञप्ति

21 जुलाई, 2012 ई0

पत्रांक 1812/आयुकर, उत्तरां0/वि0अनु0शा-अनु0/2012-13/वाणिज्य कर/दे0दून-केन्द्रीय बिक्री कर, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1957, अनुकूलन एवम् उपान्तरण आदेश, 2002, के नियम 8(14) में निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत एतद्वारा विज्ञापित किया जाता है कि (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम-1957 के नियम 12 (1) में निर्धारित घोषणा पत्र (फार्म-F) सीरीज संख्या U.K.VAT/F-2012 (क्रमांक 000001 से 100000) तक इस कार्यालय की विज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से प्रचलन में आ जायेंगे और तब तक प्रचलन में रहेंगे जब तक वे इस कार्यालय की किसी विज्ञप्ति के द्वारा अवैध अथवा अप्रचलित घोषित न कर दिये जायें।

U.K.VAT/F-2012 क्रमांक 000001 से 100000 तक सीरीज के फार्म-एफ 80 GSM के मैपलिथो पेपर पर मुद्रित है। इसकी बैक ग्राउण्ड प्रिंटिंग ऊपरी तथा निचले हिस्से में लाईट ब्ल्यू तथा बीच में लाईट पिंक की है। यह फार्म मूल प्रति 15 से0मी0, द्वितीय प्रति 15 से0मी0 एवं प्रतिपण प्रति 12 से0मी0 कुल तीन प्रतियों में 42 से0मी0×29.07 से0मी0 के साईज में दो रंगों में छापा गया है। प्रत्येक प्रति के ऊपरी हिस्से पर नारंगी कलर में उत्तराखण्ड शासन का लोगो बना है तथा फार्म की बैक ग्राउण्ड में वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड मुद्रित है। फार्मों की बैकग्राउण्ड (Background) में (कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित कठिन डिजाइन) Guilloche Pattern प्रिन्ट किया गया है। प्रत्येक प्रति के मध्य में बैक ग्राउण्ड में उत्तराखण्ड शासन का लोगो मुद्रित है।

“प्ररूप-एफ” के प्रिंटिंग में निम्नलिखित सिक्योरिटी फीचर्स डाले गये हैं:-

1. फार्मों की प्रत्येक प्रति के ऊपर की तरफ मध्य मुद्रित (Print) उत्तराखण्ड शासन का लोगो एवं फार्मों का नम्बर बॉक्स सामान्य प्रकाश में नारंगी रंग के दिखाई देते हैं तथा अल्ट्रावायलेट किरणों (U V Rays) में प्रकाशमान होते हैं।
2. फार्मों के ऊपरी भाग के मध्य में मुद्रित उत्तराखण्ड शासन के लोगों के नीचे नम्बर बॉक्स के मध्य हिस्से को काटते हुए एक अदृश्य लाईन (Invisible hide band) है, जिसमें वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड मुद्रित है, जो एण्टी फोटोकॉपियर है एवं अल्ट्रावायलेट किरणों (UV Rays) के प्रकाश में दिखाई देती है।
3. फार्मों की प्रत्येक प्रति में क्रमांक-2 में उल्लिखित अदृश्य लाईन (Invisible hide band) के नीचे दाहिनी ओर उत्तराखण्ड शासन का अदृश्य (Invisible) लोगो बना है, जो केवल अल्ट्रावायलेट किरणों (UV Rays) में ही दिखाई देता है।
4. फार्मों में UV Fiber डाले गये हैं, जो सामान्य प्रकाश में हल्के नारंगी रंग के दिखाई देते हैं तथा ये UV Fiber अल्ट्रावायलेट किरणों (UV Ray) में प्रकाशमान होते हैं।
5. फार्मों की मूल प्रति में नीचे की तरफ दायीं ओर Thermo Chromic Ink का प्रयोग करते हुए ग्रे कलर (Grey Colour) का गोला बनाया गया है, जिसमें Thumb impression देने पर (गरमी पड़ने पर) इसका रंग तुलनात्मक रूप से हल्का पड़ जाता है। पुनः impression हटा देने पर पूर्ववत् ग्रे कलर (Grey Colour) का दिखाई देगा।

विज्ञप्ति

21 जुलाई, 2012 ई0

पत्रांक 1813/आयुकर, उत्तरां0/फार्म-अनु0/12-13/वाणिज्य कर/दे0दून-केन्द्रीय बिक्री कर, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1957, अनुकूलन एवम् उपान्तरण आदेश, 2002, के नियम 8(14) में निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत एतद्वारा विज्ञापित किया जाता है कि (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम-1957 के नियम 12 (1) में निर्धारित घोषणा पत्र (फार्म-सी), U.K.VAT/C-2012 क्रमांक 0000001 से 1000000 तक इस कार्यालय की विज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से प्रचलन में आ जायेंगे और तब तक प्रचलन में रहेंगे जब तक वे इस कार्यालय की किसी विज्ञप्ति के द्वारा अवैध अथवा अप्रचलित घोषित न कर दिये जायें।

U.K.VAT/C-2012 क्रमांक 0000001 से 1000000 तक सीरीज के फार्म—सी 80 GSM के मैपलिथो पेपर पर मुद्रित है। इसकी बैक ग्राउण्ड प्रिंटिंग ऊपरी तथा निचले हिस्से में लाईट ग्रीन तथा बीच में लाईट औरेंज की है। यह फार्म मूल प्रति 15 सेमी0, द्वितीय प्रति 15 सेमी0 एवं प्रतिपर्ण प्रति 12 सेमी0, कुल तीन प्रतियों में 42 सेमी0×29.07 सेमी0 के साईज में दो रंगों में छापा गया है। प्रत्येक प्रति के ऊपरी हिस्से पर नारंगी कलर में उत्तराखण्ड शासन का लोगो बना है तथा फार्म की बैक ग्राउण्ड में वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड मुद्रित है। फार्मों की बैकग्राउण्ड (Background) में (कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित कठिन डिजाइन) Guilloche Pattern प्रिन्ट किया गया है। प्रत्येक प्रति के मध्य में बैक ग्राउण्ड में उत्तराखण्ड शासन का लोगो मुद्रित है।

“प्ररूप—सी” के प्रिंटिंग में निम्नलिखित सिक्वोरिटी फीचर्स डाले गये हैं:—

1. फार्मों की प्रत्येक प्रति के ऊपर की तरफ मध्य मुद्रित (Print) उत्तराखण्ड शासन का लोगो एवं फार्मों का नम्बर बॉक्स सामान्य प्रकाश में नारंगी रंग के दिखाई देते हैं तथा अल्ट्रावायलेट किरणों (U V Rays) में प्रकाशमान होते हैं।
2. फार्मों के ऊपरी भाग के मध्य में मुद्रित उत्तराखण्ड शासन के लोगो के नीचे नम्बर बॉक्स के मध्य हिस्से को काटते हुए एक अदृश्य लाईन (Invisible hide band) है, जिसमें वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड मुद्रित है, जो एण्टी फोटोकॉपियर है एवं अल्ट्रावायलेट किरणों (UV Rays) के प्रकाश में दिखाई देती है।
3. फार्मों की प्रत्येक प्रति में क्रमांक—2 में उल्लिखित अदृश्य लाईन (Invisible hide band) के नीचे दाहिनी ओर उत्तराखण्ड शासन का अदृश्य (Invisible) लोगो बना है, जो केवल अल्ट्रावायलेट किरणों (UV Rays) में ही दिखाई देता है।
4. फार्मों में UV Fiber डाले गये हैं, जो सामान्य प्रकाश में हल्के नारंगी रंग के दिखाई देते हैं तथा ये UV Fiber अल्ट्रावायलेट किरणों (UV Ray) में प्रकाशमान होते हैं।
5. फार्मों की मूल प्रति में नीचे की तरफ दायीं ओर Thermo Chromic Ink का प्रयोग करते हुए ग्रे कलर (Grey Colour) का गोला बनाया गया है, जिसमें Thumb impression देने पर (गरमी पड़ने पर) इसका रंग तुलनात्मक रूप से हल्का पड़ जाता है। पुनः impression हटा देने पर पूर्ववत् ग्रे कलर (Grey Colour) का दिखाई देगा।

विज्ञप्ति

21 जुलाई, 2012 ई0

पत्रांक 1814/आयु0कर उत्तरा0/फार्म—अनु0/12—13/वाणिज्य कर/दे0दून—उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 35 के अधीन कर कटौती का प्रमाण पत्र प्ररूप—8 सीरीज संख्या U.K.VAT-2012 (क्रमांक 0000001 से 1000000 तक) इस कार्यालय की विज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से प्रचलन में आ जायेंगे और तब तक प्रचलन में रहेंगे, जब तक वे इस कार्यालय की किसी विज्ञप्ति के द्वारा अवैध अथवा अप्रचलित घोषित न कर दिये जायें।

U.K.VAT-2012 (क्रमांक 0000001 से 1000000 तक) सीरीज के फार्म 80 GSM के मैपलिथो पेपर पर मुद्रित हैं। इसकी बैक ग्राउण्ड प्रिंटिंग ऊपरी तथा निचले भाग में हल्के बैंगनी कलर तथा मध्य भाग हल्के स्काई ब्ल्यू में है। यह मूल प्रति एवं प्रतिपर्ण प्रति, कुल दो प्रतियों में 42 सेमी0×29.7 सेमी0 के साईज में दो रंगों में छापा गया है। प्रत्येक प्रति के ऊपरी हिस्से पर नारंगी कलर में उत्तराखण्ड शासन का लोगो बना है तथा फार्म की बैक ग्राउण्ड में वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड मुद्रित है। फार्मों की बैकग्राउण्ड (Background) में (कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित कठिन डिजाइन) Guilloche Pattern प्रिन्ट किया गया है। प्रत्येक प्रति के मध्य में बैक ग्राउण्ड में उत्तराखण्ड शासन का लोगो मुद्रित है।

“प्ररूप-8” के प्रिंटिंग में निम्नलिखित सिक्कोरिटी फीचर्स डाले गये हैं:-

1. फार्मों की प्रत्येक प्रति के ऊपर की तरफ मध्य मुद्रित (Print) उत्तराखण्ड शासन का लोगो एवं फार्मों का नम्बर बॉक्स सामान्य प्रकाश में नारंगी रंग के दिखाई देते हैं तथा अल्ट्रावायलेट किरणों (U V Rays) में प्रकाशमान होते हैं।
2. फार्मों के ऊपरी भाग के मध्य में मुद्रित उत्तराखण्ड शासन के लोगो के नीचे नम्बर बॉक्स के निचले हिस्से को काटते हुए एक अदृश्य लाईन (Invisible hide band) है, जिसमें वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड मुद्रित है, जो एण्टी फोटोकॉपियर है एवं अल्ट्रावायलेट किरणों (UV Rays) के प्रकाश में दिखाई देती है।
3. फार्मों की प्रत्येक प्रति में क्रमांक-2 में उल्लिखित अदृश्य लाईन (Invisible hide band) के नीचे मूल प्रति में बांयी एवं दाहिनी ओर तथा प्रतिपर्ण के मध्य भाग में उत्तराखण्ड शासन का अदृश्य (Invisible) लोगो बना है, जो केवल अल्ट्रावायलेट किरणों (UV Rays) में ही दिखाई देता है।
4. फार्मों में UV Fiber डाले गये हैं, जो सामान्य प्रकाश में हल्के नारंगी रंग के दिखाई देते हैं तथा ये UV Fiber अल्ट्रावायलेट किरणों (UV Ray) में प्रकाशमान होते हैं।
5. फार्मों की मूल प्रति में मध्य भाग के नीचे की तरफ दायीं ओर Thermo Chromic Ink का प्रयोग करते हुए ग्रे कलर (Grey Colour) का गोला बनाया गया है, जिसमें Thumb impression देने पर (गरमी पड़ने पर) इसका रंग तुलनात्मक रूप से हल्का पड़ जाता है। पुनः impression हटा देने पर पूर्ववत् ग्रे कलर (Grey Colour) का दिखाई देगा।

सौजन्या,
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

विज्ञप्ति

27 जुलाई, 2012 ई0

पत्रांक 1904/आयु0कर, उत्तरा0/फार्म-अनु0/2012-13/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून-उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 30 (12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्र (प्ररूप-XVI) एवं प्ररूप-11, जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करती हूँ:-

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज व क्रमांक
1.	सर्वश्री द्वाराहाट, ग्राम स्वराज्य मण्डल, रानीबाग, काठगोदाम, हल्द्वानी	प्ररूप-11 (01)	U.A.VAT-A2006/023915
2.	सर्वश्री जुऐब खान, उजाला नगर, हल्द्वानी	प्ररूप-XVI (03)	U.K.VAT-K2010/ 1682365, 1682366, 1682367
3.	सर्वश्री श्री श्री आयुर्वेदा ट्रस्ट, सिगड्डी ग्रोथ सेन्टर, कोटद्वार	प्ररूप-XVI (01)	U.K.VAT-K2010/1282877
4.	सर्वश्री आर0आर0 इण्ड0, काशीपुर	प्ररूप-XVI (03)	U.K.VAT-K2010/ 0547430, 0547431, 0547443

कुमकुम गुप्ता,
अपर आयुक्त, वाणिज्य कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विज्ञप्ति

31 जुलाई, 2012 ई0

पत्रांक 1952/आयु0क0उत्तरा0/फार्म-अनु0/2012-13/केन्द्रीय फार्म-सी/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून-केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तराखण्ड), नियमावली, 2006 के नियम 8 के उपनियम 13 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित "फार्म-सी" जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन फार्म्स के प्रयोग को अवैध घोषित करती हूँ:-

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज व क्रमांक
1.	सर्वश्री जैन वूल एण्ड गारमेण्ट्स, पीठ बाजार, ज्वालापुर, हरिद्वार	(Form-C)--01	U.K. VAT/C-2007- 1168820

सौजन्या,
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

कार्यालय, परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
अधिसूचना

04 अगस्त, 2012 ई0

संख्या 1713/प्राविधिक/सात-1(4)/2011-12-उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 12 के उपनियम (6) में दी गई शक्तियों के अन्तर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या 877/प्राविधिक/पुनश्चर्या अनुक्रम/2012, दिनांक 17-03-2012 द्वारा व्यवसायिक वाहन चालकों के लिए रिक्रेशर कोर्स हेतु अधिकृत संस्थानों के लिये मदवार शुल्क निर्धारण किया गया है। उक्त शुल्क को अधिक युक्तिसंगत बनाये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्धारित दरों में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई, अतः उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 12 के उपनियम (6) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा सभी अधिकृत चालक प्रशिक्षण स्कूलों/संस्थानों द्वारा व्यवसायिक वाहन चालकों रिक्रेशर कोर्स (दो दिवसीय पुनश्चर्या कार्यक्रम) हेतु पूर्व कार्यालय-ज्ञाप में उल्लिखित शुल्क को संशोधित करते हुए निम्न प्रकार शुल्क निर्धारण किया जाता है:-

क्रम संख्या	विवरण	स्मार्ट क्लास हेतु शुल्क रु0	साधारण क्लास हेतु शुल्क रु0	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	प्रशिक्षण शुल्क	380.00 (अनिवार्य)	160.00 (अनिवार्य)	स्मार्ट क्लास के अन्तर्गत प्रोजेक्शन यूनिट के माध्यम से प्रशिक्षण, वातानुकूलित कक्ष, प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना सम्मिलित है
2.	दोपहर का भोजन, सुबह एवं सांयकालीन चाय	200.00 (वैकल्पिक)	120.00 (वैकल्पिक)	दिन में एक बार भोजन एवं दो बार चाय-स्नैक्स (दो दिनों के लिए) प्रशिक्षुओं हेतु उक्त सुविधा प्राप्त करने पर देय होगा

1	2	3	4	5
3.	चिकित्सीय परामर्श	100.00	100.00	रक्त समूह एवं नेत्र परीक्षण हेतु यदि आवेदक का पूर्व में नेत्र परीक्षण/रक्त समूह जाँच नहीं हुई है तो अनिवार्य
4.	दुर्घटना बीमा	70.00	70.00	₹ 1.00 लाख का दुर्घटना बीमा एक वर्ष की अवधि हेतु। यदि आवेदक बीमा कराने का इच्छुक है

डॉ० उमाकान्त पंवार,
परिवहन आयुक्त।

सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कार्यालय,
गढ़वाल सम्भाग, पौड़ी
आदेश
04 अगस्त, 2012 ई0

पत्रांक 314/सा0प्रशा0/लाईसेंस निरस्तीकरण/12-13-श्री संजय सिंह पुत्र श्री सोवन सिंह, ग्राम काण्डे, पो0 जामणाखाल पट्टी कटुलस्यूं, जिला पौड़ी गढ़वाल, जिसका लाईसेन्स संख्या 13444/पौड़ी/2007, के सन्दर्भ में पुलिस अधीक्षक, पौड़ी द्वारा अपने पत्र संख्या आर 25/2012, दिनांक 27.06.2012 के द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री संजय सिंह के विरुद्ध अल्टो कार यू0ए0-07-7919, को तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर गंगा दर्शन मोड़, पौड़ी रोड पर मोटर साईकिल संख्या यू0ए0-07 आर-9532 पर टक्कर मारकर, श्री कमल सिंह पुत्र श्री लाल सिंह को घायल कर दिया, जिसमें श्री कमल सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा श्री लाल सिंह गम्भीररूप से घायल है। उक्त पत्र में वाहन चालक के लाईसेन्स को निरस्त करने की संस्तुति की गयी है। चालक को इस कार्यालय के पत्र संख्या 240/सा0प्रशा0/लाईसेंस निरस्त/11, दिनांक 30.06.2012 द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था। चालक ने दिनांक 15.07.2012 को अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया जो कि संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः, लाईसेन्स अधिकारी के रूप में, मैं, सुनील शर्मा, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त लाईसेन्स संख्या 13444/पौड़ी/2007, को निरस्त करता हूँ।

सुनील शर्मा,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
पौड़ी।

UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

DEHRADUN

Notification No . F-9(21)/RG/UERC/2012/733

Dated: August 14, 2012

Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Tariff and Other Terms for Supply of Electricity from Renewable Energy Sources and non-fossil fuel based Co-generating Stations) (First Amendment) Regulations, 2012

STATEMENT OF OBJECTS & REASONS

1 Introduction

- (1) Section 86(1)(e) of the Electricity Act, 2003 (hereinafter referred to as "the Act") assigns the following function to the State Electricity Regulatory Commission amongst others:--
"promote co-generation and generation of electricity from renewable sources of energy by providing suitable measures for connectivity with the grid and sale of electricity to any person, and also specify, for purchase of electricity from such sources, a percentage of the total consumption of electricity in the area of a distribution licensee."
- (2) The National Electricity Policy notified by the Central Government has emphasized on the urgent need for tapping the untapped potential of energy from non-conventional and renewable energy sources. Even the Tariff Policy issued by the Central Government has provided a mechanism for promoting and harnessing renewable energy. Recognising higher costs of such sources, the Tariff Policy has mandated to provide preferential tariffs for renewable and non-conventional energy sources and guaranteed off-take of a defined percentage of power from such sources till they can compete with conventional sources.
- (3) It is, therefore, clear from the above provisions that the function of the State Commission is to promote cogeneration and generation of electricity from renewable sources of energy not only through preferential tariffs but also by providing suitable measure which influence growth of renewable energy such as:
 1. connectivity with grid for power evacuation;
 2. sale to any person; and
 3. purchase obligation as percentage of consumption in the area of Distribution Licensee.
- (4) In terms of clause (zd) of sub-section (2) of section 181 of the Act, the Commission has been vested with the powers to make regulations, by notification, on the terms and conditions of tariff under section 61. As per section 181(3) of the Act, the Commission is required to make previous publication before finalizing any regulation under the Act.
- (5) In exercise of the powers vested under sections 61 and 181(2) of the Act and all other enabling powers and in compliance of the requirement under section 181(3) of the Act, the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (hereinafter referred to as the "Commission") had notified the UERC (Tariff and Other Terms for Supply of Electricity from Renewable Energy Sources and non-fossil fuel based Co-generating Stations) Regulations, 2010 on July 06, 2010 which amongst other terms and conditions also specified the preferential tariffs for plants based on renewable sources of generation alongwith the renewable purchase obligation (RPO) for the distribution licensee for FY 2010-11 to FY 2012-13. The Commission, subsequently, also issued the UERC (Compliance of Renewable Purchase Obligation) Regulations, 2010 which provided that if the Obligated Entity does not fulfill its commitment towards Renewable Purchase Obligation during any year it can be fulfilled by purchase of renewable energy certificates.

- (6) Further, based on the difficulties expressed by UPCL and the developers of renewable energy based generating stations in interpreting, understanding and implementing certain provisions of UERC (Tariff and Other Terms for Supply of Electricity from Renewable Energy Sources and non-fossil fuel based Co-generating Stations) Regulations, 2010, the Commission had issued UERC (Tariff and Other Terms for Supply of Electricity from Renewable Energy Sources and non-fossil fuel based Co-generating Stations) Regulations, 2010, Removal of Difficulty (First) Order, 2010 on October 28, 2010.

The generators amongst other issues had raised the issue of deemed generation due to frequent tripping of the lines connecting the Generating station with the sub-station of distribution licensee, The Commission in the matter had held as under.

"Keeping in view the above concessions/relaxations allowed to RE based generating stations, the provisions of deemed generation has not been considered as necessary under the RE Regulations, 2010 in case of day to day tripping and outage of lines. However, in order to avoid bottling up of much needed generation due to inadequacy of the transmission and distribution system, the Commission is of the view that penal provisions are necessary so as to avoid such situations. This matter is under examination and the Commission shall take a final view on the same after discussions with UPCL and Developers."

- (7) For the FY 2011-12, the RPO specified for non-solar sources for UPCL was 4.50% of the total energy purchased from all sources for the purpose of supply to its consumers within its area of supply. Against this, UPCL managed to procure only 4.10% thereby implying a deficit in meeting its RPO.
- (8) The Commission was receiving continuous representations from the developers regarding frequent trippings and also voltage fluctuations in UPCL's system leading to generation loss. However, UPCL's approach was found to be lackadaisical in this regard. Proper upkeep of the distribution system to ensure maximum availability of generation was all the more crucial as it would have not only ensured additional generation to the State resorting to frequent over-drawals of power at costlier rates from the grid but would have also assisted UPCL to meet its RPO. Considering the same, the Commission decided to issue amendment to the UERC (Tariff and Other Terms for Supply of Electricity from Renewable Energy Sources and non-fossil fuel based Co-generating Stations) Regulations, 2010 to incorporate provisions relating to deemed generation. The Commission issued public notice on 24.03.2012 seeking comments/suggestions /objections of all the stakeholders on Draft UERC (Tariff and Other Terms for Supply of Electricity from Renewable Energy Sources and non-fossil fuel based Co-generating stations) (First Amendment) Regulations, 2012 (hereinafter referred to as the draft regulations). The Commission also held hearing in the matter on June 11, 2012 and June 22, 2012 for deliberations on the draft regulations. The Commission also held a meeting with MD, UPCL and ED (Commercial), UPCL on 30.07.2012 to seek their views in the matter.
- (9) In all 6 comments were received on the draft Regulations from the generators as well as UPCL. The Commission considered the comments of the stakeholders on the draft regulations. The regulations have been finalized after detailed analysis and due consideration of the various issues raised by the stakeholders.

2 Issues

2.1 Applicability

In the State of Uttarakhand, the small hydro projects are located at remote and hilly terrains, where bottlenecks related to inadequacy of the transmission and distribution system exists leading to frequent trippings, breakdowns of lines, voltage fluctuations occur leading to loss of generation. In comparison, other renewable sources are set up in plain areas close to the sub-station of UPCL where such problem may not be as persistent and as acute as that encountered for the SHP's. Further, at present only 3 Solar Generation Plants have been set up at Roorkee in the State of Uttarakhand with an installed capacity of about 5 MW and have been in operation for even less than a year. Hence, adequate data would not be available to examine the impact of the breakdowns, etc. for them. Thus, at present the Commission is only specifying the deemed generation conditions for small hydro projects. However, the Commission may consider the same for other renewable energy sources at a later stage on availability of sufficient data.

2.2 Non-availability of evacuation system beyond inter-connection point due to interruptions/outages

- (1) Some generators have pointed out that it takes approximately 90 minutes after the grid is restored to bring back the machine to full load. Hence, any outage whether for less than or more than 20 minutes may be considered towards deemed generation. Further, the generators also pointed out that the time limit of 480 hours in a year should be spread equally in 12 months and any loss beyond 40 hours/month should be considered. Few generators submitted that the time limit for grid failure of 480 hours is very high considering the fact that 40 hours will cause the generators approximately 5 to 10 times of this time. Hence, this 40 hours monthly time limit should be removed completely or at least reduced to one fourth.
- (2) The Commission discussed the issue of allowing the time limit of 20 minutes at a time and also 40 hours/month towards outages/interruptions to be excluded from deemed generation, with UPCL during the meeting. UPCL submitted that allowance of 20 minutes would be insignificant as normally breakdown in the hilly terrain, if they occur, would take about 12 hours to be restored. Hence, UPCL requested the Commission to increase the limit of 40 hours/month to 48 hours/month to cover eventualities of atleast 4 breakdowns in a month. The Commission on the request of the generators and after seeking UPCL's views on the issue has decided to do away with the time limit of 20 minutes at a time for outages/interruptions. The Commission has also increased the total duration of interruptions/outages to 48 hours/month on the request of UPCL.
- (3) Regarding, the time limit of 480 hours in a year, it is a well known fact that generation from a hydro project is seasonal, i.e. maximum during rainy season and minimum during winters. Hence, UPCL should endeavour to ensure maximum availability of evacuation system, thereby, resulting in maximization of generation by the SHPs. Further, it has been observed that major breakdowns occur in the rainy seasons with less or no breakdowns in the winters. Therefore, providing a cumulative ceiling of 480 hours, UPCL will not be inclined to put in extra efforts to ensure maximum availability of evacuation system to maximize generation during the rainy season when the water availability is also maximum. Thus, the Commission has decided to do away with the annual limit of 480 hours and has instead decided to have a monthly limit of 48 hours/month.

The illustrations given below would explain the computation of generation loss due to grid interruptions/outages.

Illustration 1: Computation of month-wise deemed generation due to interruptions/outages

- i. Project having an installed capacity of 8 MW.
- ii. Total number of hours available during the month (A) = 720 hours
- iii. Total hours of hours of outage/interruption in the system during the month (B) = 50 hours
- iv. Number of hours to be considered for deemed generation purposes = $50 - 48 = 2$ hours
- v. Total actual generation achieved during the month = 2.28 MUs
- vi. Deemed generation (MU) = $2.28 \times 2 / (720 - 50) = 0.0068$ MU

Illustration 2: Computation of annual deemed generation due to interruptions/outages

For 8 MW project, deemed generation based on actual CUF achieved during the year, actual number of month-wise outages/interruption in the system during the year is given as under:

<i>Month</i>	<i>Total actual generation achieved during the month (MU)</i>	<i>Total hours of outage/interruption in system during the month</i>	<i>Number of hours to be considered for deemed generation purposes</i>	<i>Deemed generation (MU)</i>
<i>(a)</i>	<i>(b)</i>	<i>(c)</i>	<i>(d)=(c)-48</i>	<i>(e) = (b)*(d)/(No. of hours in a month--c)</i>
<i>April</i>	2.28	50	2	0.0068
<i>May</i>	2.59	52	4	0.0150
<i>June</i>	2.74	60	12	0.0498
<i>July</i>	2.95	75	27	0.1191
<i>August</i>	3.30	90	42	0.2119
<i>September</i>	3.14	80	32	0.1570
<i>October</i>	2.95	60	12	0.0518
<i>November</i>	2.57	0	0	0.0000
<i>December</i>	2.36	60	12	0.0414
<i>January</i>	2.12	46	0	0.0000
<i>February</i>	1.97	0	0	0.0000
<i>March</i>	2.12	42	0	0.0000
Total	31.07			0.6527

2.3 Voltage Fluctuations

- (1) Regarding the issue of voltage fluctuations raised by the generators, the Commission recognises that the problem of voltage fluctuations in UPCL's system is rampant which often causes generation loss. This issue was also discussed by the Commission during the meeting with senior officers of UPCL. They admitted that this problem exists because of the evacuation lines running for long distances, improper load management and also due to poor upkeep and maintenance of the equipments installed at the sub-stations. The Commission accepted the submission of UPCL, however, UPCL was instructed to maintain their equipments properly and also to ensure installation of capacitor banks at the sub-stations, wherever required, so as to ensure that voltage fluctuations does not lead to generation loss. It is the duty of UPCL to ensure that it gets maximum generation so as to meet its Renewable Purchase Obligation (RPO) specified by the Commission failing which it may be required to buy the Renewable Energy Certificates to meet the shortfall in complying with its RPO. Hence, the Commission feels it necessary to include loss of generation due to voltage fluctuation as deemed generation. However, keeping in view the existing system of UPCL, the Commission is of the view that it would be feasible to give UPCL reasonable time to upgrade/strengthen the system and also to install the capacitor banks at its sub-stations. The same was also agreed to by the officers of UPCL in the meeting with the Commission. Accordingly, the Commission has decided to enable the provision with regard to deemed generation on account of voltage fluctuations w.e.f. 01.04.2013.

- (2) The Commission has, accordingly, decided to include the following in the amended Regulation:

“UPCL shall be required to maintain the voltages at the point of interconnection with the project within the limits stipulated hereunder, with reference to declared voltage:

a) In the case of High Voltage, +6% and -9%; and,

b) In the case of Extra High Voltage, +10% and -12.5%.

With effect from 01.04.2013, any loss in generation due to variations in the voltage beyond the limits specified above shall be reckoned as deemed generation.

Provided that any loss in generation due to variation in voltage beyond the limits specified above, should be atleast 25%.”

Here, the generation loss of 25% has been provided, keeping in view that for a plant having 4 units, atleast one unit should have tripped/stopped due to voltage fluctuations resulting in appreciable loss of generation due to voltage fluctuations.

For a plant running at a load of 8 MW before voltage variations/fluctuations occurred, the loss in generation due to variation in voltage beyond the limits specified, will be considered for deemed generation purposes only if the generation drops to 6 MW or below after voltage variations/fluctuations occurred.

- (3) Further, the calculation of generation loss due to voltage fluctuations included in deemed generation would be carried out in the following manner:

“The generation loss towards the Deemed Generation (in MWh) in accordance with sub-Regulation (2) above, if any, during the month shall be considered as the summation of the product of number of hours the variations in voltage beyond the specified limit existed and the Generation lost (in MW) due to the variation in the voltage beyond the specified limit. The Generation lost (in MW) would be the difference between the following:

a. Minimum of the actual generation (in MW) before the variation in voltage occurred and the generation (in MW) achieved after 90 minutes immediately after variation in voltage was restored within the specified limit would be treated as the actual generation during the period when voltage variations occurred; and

b. The generation achieved during the period when variation in voltages took place.”

- (4) The rationale behind taking generation after 90 minutes immediately after each fluctuation/variation in voltage was restored within the specified limit is that, some of the generators submitted that it takes about 70-95 minutes after the grid is restored to bring back the machine to full load. The Commission understands that the meters installed at their stations are ABT Compliant meters which can be read through MRI's. Hence, the Commission has decided to consider the generation achieved after 90 minutes immediately after variation in voltage was restored within the specified limit as it would enable the generator to bring the plant to maximum possible load.

The illustration given below would explain the computation of generation loss due to voltage fluctuations included in deemed generation.

Illustration 3: Computation of generation loss due to voltage fluctuations/variations included in deemed generation considering a case of one instance of variation during the month of April

- i. Actual generation before voltage variation/fluctuation occurred = 6.00 MW
- ii. Generation during the period when variation in voltages took place
 - a. 3.50 MW for half an hour
 - b. 2.50 MW in next half hour
- iii. Duration of Voltage Fluctuation/Variation
 - a. Ist Variation for half an hour
 - b. IInd variation for next half hour
- iv. Generation achieved after 90 minutes immediately after voltage was restored within the specified limit = 5.00 MW
- v. Actual Generation to be considered for generation loss = MIN of (i) & (iv) = 5 MW
- vi. Deemed Generation (MWh) = [(iii(a)) X (v-ii(a)) + [iii(b)) X (v-ii(b))]] = $1/2 \times (5.00-3.50) + 1/2 \times (5.00-2.50) = 0.75 + 1.25 = 2.00$ MWh

Illustration 4: Computation of Yearly generation loss due to voltage fluctuations/variations included in deemed generation for a 8 MW project :

Month	Total actual Saleable generation achieved during the month (MU)	Deemed generation (MWh)
(a)	(b)	(c)
April	2.28	0
May	2.59	8
June	2.74	16
July	2.95	0
August	3.30	10
September	3.14	0
October	2.95	8
November	2.57	9
December	2.36	3
January	2.12	2
February	1.97	3
March	2.12	2
Total	31.07	61

Illustration 5: Adjustment of deemed generation

- a. Total Annual Saleable energy at CUF of 45% = 31.22 MU
- b. Actual Annual Saleable Generation = 31.07 MU
- c. Deemed Generation due to non-availability of evacuation system beyond inter-connection point (From Illustration 2) = 0.6527 MU
- d. Deemed Generation due to voltage fluctuation (From Illustration 5) = 61 MWh = 0.061 MU
- e. Total deemed generation = $0.6527+0.061= 0.7137$ MU
- f. Sum of actual annual saleable generation and total deemed generation (b+e) = $31.07+0.7137= 31.7837$ MU

Here, since the actual saleable energy during the year is less than the CUF of 45%, the generator is eligible for the deemed generation under the amended Regulation. Further, since the sum of actual annual saleable generation and total deemed generation of 31.7837 MU is more than the annual saleable energy of 31.22 MU at CUF of 45%, therefore, deemed generation of only 0.15 MU would be allowed in addition to the actual saleable energy of 31.07 MU equivalent to the specified ceiling of 45% CUF.

Further, it would also be relevant to mention that any charges paid by UPCL towards deemed generation shall not be allowed as an expense to be pass through in tariffs. Since, the deemed generation would be applicable due to the inefficiency of UPCL, and any inefficiency cannot be rewarded by allowing it as pass through in tariffs, hence, it will have to bear such charges.

2.4 Retrospective Applicability

- (1) One of the generators has submitted that the generators are suffering heavily due to grid failure, voltage fluctuations and rostering carried out by UPCL. Hence, this benefit should be made available retrospectively from 06.07.2010 for old projects.
- (2) In this regard, it would be pertinent to mention that Regulation cannot be applied retrospectively. It is held by the Hon'ble Supreme Court in the case of State of Madhya Pradesh V/s Tikamdas (1975) 2 SCC 100 that subordinate legislation cannot be given retrospective effect unless specifically so authorized under the parent statute. The relevant observation made by the Hon'ble Supreme Court is as follows:

“There is no doubt that unlike legislation made by a sovereign legislature, subordinate legislation made by a delegate cannot have retrospective effect unless the Rule-making power in the concerned statute expressly or by necessary implication confers power in this behalf”

- (3) Further, the Hon'ble Appellate Tribunal of Electricity in its Judgment dated July 12, 2010 in Appeal No. 179 of 2009 has also observed as under:

“The Electricity Act, 2003 under which regulations are being framed by the respective Commissions does not permit the Commission to make regulations which may apply retrospectively.”

Thus, the amendment Regulation would be applicable only from the date of notification.

In exercise of powers conferred under section 181 of the Electricity Act, 2003, and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Tariff and Other Terms for Supply of Electricity from Renewable Energy Sources and non-fossil fuel based Co-generating stations) Regulations, 2010 (Principal Regulations), namely:

1. Short Title, Commencement and Interpretation

- (1) These Regulations may be called the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Tariff and Other Terms for Supply of Electricity from Renewable Energy Sources and non-fossil fuel based Co-generating stations) (First Amendment) Regulations, 2012.
- (2) These Regulations extend to the whole of the State of Uttarakhand.
- (3) These shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. After Regulation 3(1)(i) of the Principal Regulation the following shall be added:-

- (i)(a) "Force Majeure Event" means, with respect to any party, any event or circumstance which is not within the reasonable control of, or due to an act or omission of, that party and which, by the exercise of reasonable care and diligence, that party is not able to prevent, including, without limiting the generality of the foregoing:
 - i. Lightning, storm, earthquakes, flood, natural disaster and action of the natural elements;
 - ii. acts of public enemy, blockades, insurrections, riots, revolution and sabotage;
 - iii. unavoidable accident, including but not limited to fire, explosion, radioactive contamination and toxic dangerous chemical contamination;

3. After Regulation 44 of the Principal Regulation the following shall be added:-

44 (A) Deemed Generation:

- (1) After the COD of the Project, loss of generation at the Station on account of reasons attributed to the following, or any one of the following, which results in Water Spillage, shall count towards Deemed Generation:

-- Non availability of evacuation system beyond the Interconnection Point; and

-- Receipt of backing down instructions from the SLDC.

Provided that the following shall not count towards Deemed Generation:

- (i) the loss of generation at the Station on account of aforesaid factor(s) but attributed to the Force Majeure event(s);
 - (ii) the loss of generation at the Station due to the interruptions/outages attributed to the aforesaid factor(s) during the period in which the total duration of such outages/ interruptions, other than that excluded under (i) above, is within the limit of 48 hours in a month; and
- (2) UPCL shall be required to maintain the voltages at the point of interconnection with the project within the limits stipulated hereunder, with reference to declared voltage:
 - a) In the case of High Voltage, +6% and -9%; and,
 - b) In the case of Extra High Voltage, +10% and -12.5%.

With effect from 01.04.2013, any loss in generation due to variations in the voltage beyond the limits specified above shall be reckoned as deemed generation:

Provided that any loss in generation due to variation in voltage beyond the limits specified above, should be atleast 25%.

- (3) The period of outage/interruption on account of such factor(s) specified in sub-Regulation 1 and 2 above, shall be reconciled on monthly basis and the loss of generation at the Station towards Deemed Generation after accounting for the events specified under sub-Regulation (1) (i) & (ii) above, shall be computed on following considerations:--
- (i) The recovery on the above account shall be admissible if the actual energy generated during the year is less than the normative CUF of 45%, specified for recovery of fixed charges for small hydro projects. In case the sum of actual energy generated and the deemed generation during the year exceeds the normative CUF specified of 45%, then the deemed generation alongwith the actual energy generated will be allowed only upto the CUF of 45%.
 - (ii) The generation loss towards the Deemed Generation in accordance with sub-Regulation (1) above, if any, during the month shall be considered on the pro-rata basis on the number of hours lost based on the actual average generation achieved during that month divided by the total number of hours available during the month reduced by the number of hours outage/interruption occurred in the system.
 - (iii) The generation loss towards the Deemed Generation (in MWh) in accordance with sub-Regulation (2) above, if any, during the month shall be considered as the summation of the product of number of hours the variations in voltage beyond the specified limit existed and the Generation lost (in MW) due to the variation in the voltage beyond the specified limit. The Generation lost (in MW) would be the difference between the following:--
 - a. Minimum of the actual generation (in MW) before the variation in voltage occurred and the generation (in MW) achieved after 90 minutes immediately after variation in voltage was restored within the specified limit would be treated as the actual generation during the period when voltage variations occurred; and
 - b. The generation achieved during the period when variation in voltages took place.
- (4) UPCL shall pay for the saleable deemed generation, on annual basis, for small hydro projects worked out on the basis of the deemed generation on the above lines, at the generic/project specific tariffs under the provisions of RE Regulations, as amended from time to time by the Commission. The settlement of payment towards deemed generation charges shall be carried out within 3 months of the completion of the financial year.
- (5) Any charges paid by UPCL towards deemed generation shall not be allowed as an expense to be pass through in tariffs. UPCL will have to bear such charges.
- (6) The deemed generation conditions stipulated above shall be applicable only on those small hydro projects who have signed a long term PPA with UPCL on the preferential tariffs specified in the Principal Regulations.
- Further, the deemed generation conditions shall be applicable only on the small hydro projects where the evacuation line is connected to 11 kV or higher voltage Grid Sub-station.
- (7) The deemed generation conditions as stipulated above shall come into effect from the date of publication of the amendment regulation in the Government Gazette.

By the order of the Commission,

Neeraj Sati,
Secretary.